भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2820

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

नई मोबाइल विनिर्माण पहल

2820. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई मोबाइल विनिर्माण पहल के अंतर्गत उच्च घरेलू मूल्यवर्धन, डिजाइन क्षमताओं और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए हैं;

(ख) इस पहल के अंतर्गत अनुसंधान, नवाचार और घटक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्च स्तर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का विस्तार करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण करने के लिए श्रीपेरंबदूर और होसुर सहित तमिलनाडु में विनिर्माण केन्द्रों की संभाव्यता का आकलन किया है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करने और प्रौद्योगिकी विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं।

सरकार ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एक सुविचारित रणनीति अपनाई - जिसकी शुरुआत तैयार उत्पादों के विनिर्माण से हुई, इसके बाद उप-संयोजन, घटकों और अंततः मशीनरी और उपकरण शामिल हुए। साथ ही, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को समर्थन देने के लिए आवश्यक अवसरंचना के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।

इन पहलों के परिणामस्वरूप, भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। पिछले 12 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में काफी विस्तार हुआ है, जिसे निम्नलिखित आंकड़ों से अवलोकित किया जा सकता है:

#	2014-15	2025-26	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (₹)	~1.9 लाख करोड़	~13.11 लाख करोड़	7 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (₹)	~38 हजार करोड़	~4.24 लाख करोड़	11 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का उत्पादन (₹)	~18 हजार करोड़	~6.27 लाख करोड़	33 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का निर्यात (₹)	~15 सौ करोड़	~ 2.59 लाख करोड़	165 गुना वृद्धि

मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक घटकों सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू उत्पादन, निर्यात और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों

के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि संभव हुई है। कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना
- आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0
- इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस)
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (स्पेक्स)
- भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम।
- भारत में विनिर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश।
- इस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति

मोबाइल फोन देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में समग्र विकास के लिए मुख्य बिंदु रहे हैं। मोबाइल फोन ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन विनिर्माता के रूप में उभरा है और वर्ष 2014 में मोबाइल फोन के आयातक से मोबाइल फोन के निवल निर्यातक में परिवर्तित हो गया है। मोबाइल फोन विनिर्माण वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विनिर्माण के लिए आवश्यक पैमाने और क्षमता प्रदान कर रहा है।

<u>मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस)</u>

मोबाइल फोन विनिर्माण को और बढ़ाने, घरेलू मूल्यवर्धन को गहरा करने, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को सुदृढ़ करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए 62,500 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ दिनांक 15.07.2026 को मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) को मंजूरी दी।

एमपीएमएस का उद्देश्य 2.25% से 5% तक के अलग-अलग प्रोत्साहनों के साथ मोबाइल फोन उत्पादन को प्रोत्साहित करके मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ाना है। देश में मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम को सुदृढ़ करके घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) को बढ़ाने के लिए, यह योजना प्रमुख घटकों और उप-संयोजनों की घरेलू सोर्सिंग पर 1.5% तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों को भारतीय डिजाइन और अनुसंधान एवं विकास के लिए 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), नवाचार पर जोर देकर और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करके भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों का विनिर्माण करना है।

<u>इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस):</u>

देश में एक सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) पहले ही शुरू कर दी है। यह योजना प्रमुख

घटकों और उप-असेंबलियों जैसे मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी), ली-आयन सेल, बाड़ों, निष्क्रिय घटकों और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घटकों, डिस्प्ले मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल और ऑप्टिकल ट्रांसीवर; उनकी आपूर्ति श्रृंखला; और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरण के विनिर्माण का समर्थन करती है।

<u>तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण</u>:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण से तमिलनाडु को लाभ हुआ है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के तहत तमिलनाडु में कई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना का समर्थन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

#	**जिला**	**विनिर्माण इकाइयों की संख्या**
1	चेंगलपट्टू	4
2	चेन्नई	6
3	कोयंबटूर	1
4	कांचीपुरम	38
5	कृष्णागिरी	8
6	थूथुकुडी	2
7	तिरुनेलवेली	1
8	तिरुवल्लूर	6
9	वेल्लोर	1

ये इकाइयां मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर उत्पादों, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, पूंजीगत सामान, पीसीबी, डिस्प्ले मॉड्यूल, बाड़ों, ट्रांसड्यूसर, एलईडी लाइट्स, चार्जर, कनेक्टर आदि के विनिर्माण में कार्यरत हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0): सेटअप समय को कम करने और उत्पादन दक्षता बढ़ाने के लिए तैयार भूमि, उपयोगिताओं और सामान्य सुविधाओं के साथ प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण अवसरंचना प्रदान करने के लिए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना को अधिसूचित किया।

ईएमसी 2.0 योजना के तहत, तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में दो (02) ग्रीनफील्ड ईएमसी अनुमोदित किए गए हैं। इन परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 1012.02 करोड़ रुपये है, जो 506 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्त सहायता के साथ 853.6 एकड़ क्षेत्र को कवर करती है।

*****